

संपादकीय

हमें जनगणना की जरूरत क्यों है

प्रति व्यक्ति सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) घटकर 'एक्स' फीसदी हो गया है; 18 से 44 आयु-वर्ग में जोखिम का खतरा 'वाई' फीसदी रहता है; उत्तर प्रदेश में 'जेड' लाख ग्रामीणों को अब तक बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी है- इस तरह की सुरियोंगां आप जोना अखबारों में पढ़ते हैं। मगर क्या कभी आपने यह सोचा है कि भला कैसे कोई लेखक 'एक्स', 'वाई' या 'जेड' जैसे सटीक आंकड़े जान लेता है, जबकि इसके लिए संबंधित इलाके के हर व्यक्ति की गिनती भी नहीं की जाती? दरअसल, संबंधित इलाके, राज्य अथवा देश के कुछ लोगों से जानकारियां इकट्ठा करके यह आकलन किया जाता है, और आवादी के इस छोटे या सैंपल डाटा को दिखाने के लिए जिस बड़े आंकड़े को आधार बनाया जाता है, वह है देश की दशकीय जनगणना। 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर करीब-करीब पूरा कब्जा कर लिया था। 1858 में, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण कंपनी से लेकर ब्रिटिश राजशाही को सौंप दिया गया। मगर शासन स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को लोगों और उनकी रिहाइश को लेकर विस्तृत और विश्वसनीय डाटा की जरूरत थी। आखिरकार, वह कैसे तय कर सकती थी कि उनकी महारानी ने भारत पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो अमानवीय टैक्स लगाया है, वह देश के हर निवासी से वसूला जाए?

आपानवाशक सत्ता का पता था जो क्या करना है। वह 1801 से ही इस अपने यहाँ कर रही थी। इस कवायद को 'सेस्सस', यानी जनगणना कहा गया, जो लैटिन शब्द 'सेसेर' से निकला है। रजिस्ट्रर जनरल एंड सेस्सस कमिश्नर के कार्यालय बनाए गए और 1881 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। बेशक जनगणना का मूल उद्देश्य जबरन वसूली की मशा को पूरा करना था, लेकिन इसका लाभ कई विभागों को मिला। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा की अपनी योजना बनाने में इसका इस्तेमाल किया। लोक-निर्माण विभाग ने इसका उपयोग सड़क नेटवर्क की योजना बनाने में किया। विजली संयंत्र स्थापित करने और प्रिड तक ट्रक लाइन लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और, रेलवे ने पटरियां बिछाने की योजना बनाने में इसका उपयोग किया। जनगणना के आंकड़ों ने जैसे ही बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया, लोगों की बढ़े पैमाने पर आवाजाही बढ़ गई। बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह वाले शहरों का तेज विकास हुआ, क्योंकि रेल नेटवर्क से उन्हें निकट और सुरु लिलाकों से जोड़ा गया।

औपनिवेशिक राज की ईर्पणराईं 1947 के बाद भी कायम रहीं। सौभाग्य से जनगणना भी उनमें से एक है। अमूमन पांच या दस साल पर होने वाली जनगणना को राष्ट्रीय संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य माना जाता है। अमेरिका दशक के अंत में जनगणना करता है, जो 2020 में कोविड-19 के बावजूद पूरा किया गया, तो चीन ने भी पिछले साल अपनी दशकीय जनगणना पूरी की है। भारत में पिछ्ली बार 2010 में गिनती शुरू हुई थी, जो 2011 में पूरी हुई। अपने यहां इसका बुनियाद परिवार सर्वे है। मगर यह सर्वे पिछले साल जैसे मृतप्राय रहा। अब तो हम 2021 के मध्य में आ चुके हैं, लेकिन जनगणना का अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सवाल है, 2021 की जनगणना की परवाह आखिर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? पहली बजह, अब हम यह जानते हैं कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन का जितना ॲडर्ड दिया, वह आबादी के घनत्व को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सका था। जनगणना से न सिर्फ हमें यह पता होता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि उनकी उम्र, लिंग, मूल निवास, परिवार और शिक्षा का स्तर भी हम जान लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में ऐसे सभी विवरण मौजूद हैं, जनगणना होने पर 2021 में भी ये हमारे पास होते।

मान्यूद ह, जनगणना हानि पर 2021 म भा य हमार पास होत। दूसरा कारण, 2026 में अगली परिसीमन प्रक्रिया के खत्म होने पर लोकसभा में राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा। यदि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है, तो जिन राज्यों में जनसंख्या प्रबंधन की हालत खस्ता है (विशेष रूप से हिंदी पड़ी में), संसद में उनकी नुमाइंदगी काफी बढ़ जाएगी। दक्षिण व पश्चिम भारत को नुकसान होगा। जाहिं है, परिसीमन के लिए भी हमें जनगणना के तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। तीसरा, सघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की वित्त आयोग निगरानी करता है। वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी इस वितरण को और विवादाप्त बना देता है। राजस्व के निर्धारण में भी जनसंख्या अहम भूमिका निभाती है। चौथा, देश में सांप्रदायिक राजनीति जारी है। कई नेता यह आरोप लगाते हैं कि बहुसंख्यक आबादी घट रही है और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जमीनी हकीकत जानने के लिए जनगणना एक अखिल भारतीय प्रक्रिया है। यह न सिर्फ हमें आबादी की संख्या बताती है, बल्कि जन्म व मृत्यु दर, प्रजनन दर, सकल और शुद्ध जन्म दर, नवजात मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर जैसे आंकड़े भी हमारे सामने रखती है। ध्रुवीकरण की राजनीति को जनगणना बेपरवा कर सकती है। पांच, आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की बात चल रही है। आखिर उन निवेशों का आधार क्या होगा? इससे जुड़े कई सवाल हैं, जैसे- अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन क्या एक अच्छी योजना है? किन रेल मार्गों को और मजबूत करने की दरकार है? सड़क, नदी, समुद्री और हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे को किस तरह से सुधारा जाना चाहिए? किसानों को अपनी उपज पर पर्याप्त फायदा कैसे मिलेगा? सबसे अच्छा मॉडल क्या है? जनगणना इन तमाम सवालों का उत्तर जवाब दे सकती है, जिससे योजनाकारों को यह पता चलेगा कि इन सबसे कौन लाभान्वित होगा, कितना होगा और किस कीमत पर होगा? और आखिरी कारण, सामाजिक जीवन में टीवी जिस तरह से शामिल है, उसे देखते हुए क्या हम यह कह सकते हैं कि बार्क रेटिंग चैनलों या टेलीविजन शो के देखने का असल पैटर्न बताती है? क्या 2021 में ग्रामीण दर्शक वार्क ईशाही दर्शकों से ज्यादा हो जाएगे? व्हाइग पैनल द्वारा बार्क डाटा जमा करती है, और जनगणना के आधार पर रेटिंग तय करती है। जब जनसंख्या का आंकड़ा ही गलत है, तो रेटिंग क्या सही हो सकती है?

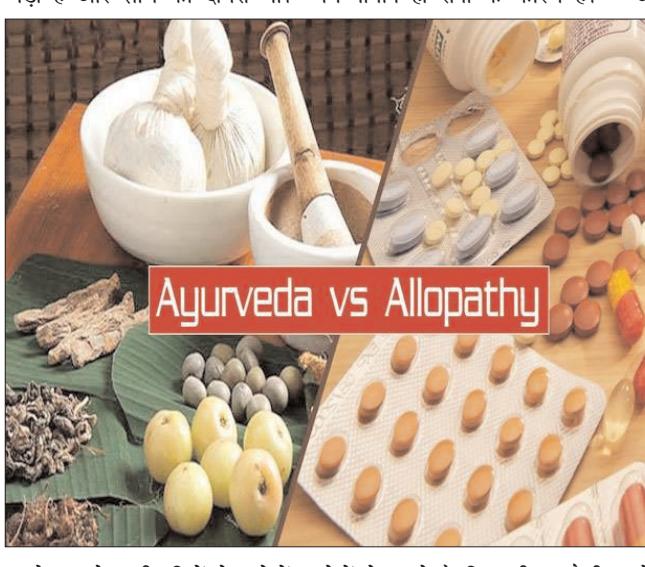
भारत सरकार द्वारा इतना कोविड टीके का बड़ा ऑर्डर देने की वजह टीकाकरण की आपूर्ति बढ़ाने में हो रही मुश्किलें हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने फाइजर, एस्ट्रोजेनेका और मॉर्डना जैसे टीकों में अग्रिम भुगतान और जोखिम वाले निवेश किए थे, भारत सरकार ने सीमित ऑर्डर देने से पहले भारत में दोनों टीकों को नैदानिक परीक्षण की आधिकारिक मंजूरी मिलने तक इंतजार किया। हमारे देश को दिसंबर तक कोविड के टीकों की 200 करोड़ खुराक तक सुरक्षित करना होगा। इस लक्ष्य को देखते हुए कॉर्बेक्वैक्स इस अपेक्षित आपूर्ति का एक बड़े हिस्से का उत्पादन कर सकेगा। इस प्रकार से ये करार ऐतिहासिक है और भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी परा करता नजर आता है।

कॉर्बेंवैक्स एक 'रेकॉर्डीनेट प्रयुनिट' टीका है जिसका अर्थ कोरोनावायरस के एक विशिष्ट भाग की सतह पर पाई जाने वाली स्पाइबना है। जैसा कि विदित है, स्पाइबायरस को हमारे शरीर की कोशिकाएँ करने में मदद करती हैं। इसके बाकोशिकाओं के अंदर अपनी संख्यावृद्धाते हुए हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है। यह प्रोटीन टीके के रूप में शरीर में जरिए दिया जाएगा तो इसके हानिकारक उम्मीद कम है, क्योंकि ये अकेला वायरस के अन्य भागों के लिए रोगकारी सकता है। इस प्रकार से इंजेक्शन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ शरीर में प्रतिक्रिया विकसित होने की उम्मीद जब असली विषाणु शरीर को संक्रमित प्रयास करेगा, तो शरीर में पहले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तैयार होगी जिससे गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका यद्यपि इस तकनीक का उपयोग हेपेटाइटिस-बी के टीके बनाने के जाता रहा है। फिर भी कॉर्बेंवैक्स का उपयोग करने वाले पहले कोविड एक होंगा। इसी तकनीक पर आधारित इस कंपनी का बनाया हुआ एक टीका विभिन्न नियमों से आपातकाल प्राधिकरण की स्वीकृत की प्रतीक्षा जबकि कॉर्बेंवैक्स स्वदेशी रूप होगा।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद में कोई प्रतिरूपी नहीं, दोनों का उद्देश्य मानवता का स्वास्थ्य है

दोनों का विकास
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
दुआ है। दोनों विज्ञान हैं।
दोनों की सीमा भी है।
डायबिटीज से विश्व का
बड़ा भाग पीड़ित है। इस
रोग को समाप्त करने की
दवा नहीं है। दोनों
प्रणालियों को मिलाने
की जरूरत है। कुछ
बीमारियों का उपचार
पहले आयुर्वेद को सौंपा
जा सकता है। इसी तरह
कुछ रोगों का प्रारंभिक
उपचार आधुनिक
चिकित्सा विज्ञानी करें।
बाद का उपचार
आयुर्विज्ञानी करें। दोनों
के विशेषज्ञों में सतत
संवाद चलते रहने की
व्यवस्था करनी चाहिए।
प्राचीनता और
आधुनिकता का संगम
आष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों
में फलप्रद होता है।

स्वस्थ जीवन और दीर्घ सर्वोच्च अभिलाषा है। रोग र जीवन और स्वस्थ जीवन में ३ है। रोगी शरीर में अंतर्संगीत होता। आयुर्वेद आचार आधार आयुर्विज्ञान है और एलोपैथी उपचार आधारित चिकित्सा विज्ञान। स्वजीवन के लिए दोनों उपचारों के लेकिन यहाँ दोनों के समान विद्वानों में परस्पर भिड़त है। इसका रहस्यपूर्ण संरचना है। इसका आनंदिक गतिविधि का बड़ा जान लिया गया है। चिकित्सानियों को इसका श्रेय आयुर्वेद का जन्म लगभग 40 वर्ष ईंपूर क्रष्णवेद के रचनाकाल हुआ और विकास अथवा (3000-2000 ईपू) मैकडनल और कीथ ने 'वैद्य इंडेक्स' में लिखा है, 'भारतीयों रुचि शरीर रखना संबंधी प्रश्नों ओर बहुत पहले से थी। अथवा में अनेक अंगों के विवरण हैं यह गणना सुव्यवस्थित है।' लेखकों ने आयुर्वेद के दो आचार चरक और सुश्रुत का उल्लेख किया है। यूरोप में एलोपैथी का विवरण 16वीं-17वीं सदी के आसपास



Ayurveda vs Allopathy

A close-up photograph of various pharmaceutical tablets and capsules of different colors (yellow, red, brown) scattered on a light-colored surface. A white plastic bottle is visible in the background.

की दवा बताई जाती है। चिकित्सक इसे हार्ट अटैक से बचने की दवा बताते हैं। आयुर्वेद में रक्त तरलता की औषधियां हैं। आधुनिक चिकित्सा में साइड एफेक्ट बड़ी समस्या है। तमाम एलोपीथिक औषधियां रोग के साथ रोगी को भी पीटती हैं। रोगी को तत्काल राहत के लिए ऐसी औषधियों की उपयोगिता है। स्ट्रायड खतरनाक दवा है। कह सकते हैं कि इसका प्रभावी विकल्प नहीं है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में विकल्पहीनता उचित नहीं। ऐसे मामलों में शोध की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संसूचित रहता है। पहले शोध और फिर किन्हीं जीवों पर प्रभाव का आकलन। फिर मनुष्यों में फलप्रद होता है। चिकित्सा और रोगोपचार के क्षेत्र में दोनों के विशेषज्ञ मिलकर शोध करें। आरोप-प्रत्यारोप का कोई औनियत्व नहीं है।

ਮਹਾਂਗਾਈ ਨੇ ਬਢਾਈ ਮੁਸੋਬਤ

म गुद्दस, कमांडटी और केक्ट के कारण मई में थोक 12.94 फीसदी और गाई दर 6.30 फीसदी तक ज्ञाद है। यह बुरी खबर है इससे आरबीआई पर व्याज बढ़ती करने का दबाव है बात और है कि वह ऐसा क्योंकि असल चिन्ता ग्रोथ बढ़ने की है। कोरोना वजह से लॉकडाउन और नमी आने के कारण ग्रोथ बनी हुई है। दूसरी तरफ, रिका और अन्य अमीर देशों में गतिविधियां तेज हो रही हैं, कच्चे तेल और दूसरी के दाम और बढ़ेगे। यानी आरबीआई के लिए ग्रोथ गाई दर के बीच संतुलन नहीं होगा। कमांडटी दाम से उद्योग-धंधों पर भी पड़ेगा क्योंकि उनके लिए तेल की लागत बढ़ जाएगी। युफिकर्ड गुद्दस और महंगे कोर इन्प्लेशन कहते हैं। लियम गुद्दस और खाने-पीने के दर शामिल नहीं होती। मई छठे 83 महीनों में सबसे थी। इसका मतलब यह है कि कच्चे माल की बढ़ी हुई बोझ ग्राहकों पर डाल रही नतीजों का विश्लेषण किया तो पता चला कि उन्हें 1.8 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह उनके प्रॉफिट मार्जिन में बढ़तीरी है। यह मार्जिन उन्हें सामान के दाम बढ़ाने से मिल रहा है। इसे हेल्दी नहीं माना जा सकता क्योंकि महामारी के कारण उद्योग-धंधों के बंद होने या कम उत्पादन, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने और पगार घटने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटी है। आम ग्राहकों के लिए बुरी खबर इतनी ही नहीं है। खुदरा महंगाई दर में खाने के सामान की महंगाई मई में 5.01 फीसदी रही, जो इससे पिछले महीने सिर्फ 1.96 फीसदी थी। इसमें खाने का तेल और दाल की कीमतों का बड़ा योगदान है खाने के सामान के साथ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई से गरीबों पर सबसे अधिक चोट पड़ रही है। इससे दूसरी जरूरतों पर खच करने के लिए उनके पास कम पैसा बच रहा है। यही हाल रहा तो इससे खपत और घटेगी, जिसका ग्रोथ पर बुरा असर होगा। केंद्र और राज्य चाहें तो पेट्रोलियम गुद्दस पर टैक्स घटाकर लोगों को फौरन महंगाई से राहत दे सकते हैं। पेट्रोल के दाम में 61 फीसदी और डीजल में 54 फीसदी टैक्स के मद में जाता है इससे लोगों, कारोबारियों और रिजिव बैंक को राहत मिलेगी, कर्ज सस्ता बना रहेगा, खपत को मजबूती मिलेगी। इसके साथ, केंद्र को अधिक गतिविधियां तेज करने के लिए राहत पैकेज लाने पर भी विचार करना चाहिए।

आत्मनिर्भरता की ओर कोविड टीका निर्माण, कम लागत में प्रभावी टीका निर्माण में मिल रही कामयाबी



कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रायोपिकल मेडिसिन में हुआ था। वहां के वैज्ञानिक एक दशक से दूसरे कोरोना वायरस सार्स और मर्स के लिए रेकॉम्बिनेंट प्रोटीन बाले टीकों पर काम कर रहे थे। वहां के प्रोफेसर और सकाय अध्यक्ष डॉ पीटर होटेज का कहना है, 'हम उच्च स्तर की दक्षता के साथ कोरोना वायरस के लिए एक रेकॉम्बिनेंट प्रोटीन (बाला टीका) बनाने के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को जानते थे।' जब फरवरी 2020 में कोरोना वायरस का

करने वाले जीन के अनुक्रम को निकाला और इसके बाद इसकी क्लोनिंग और इंजीनियरिंग पर काम किया। इसके बाद जीन को खमीर की कोशिका में डाल दिया गया, ताकि वह स्पाइक प्रोटीन अणु की प्रतियां बना सके और जारी कर सके।

जैव-प्रौद्योगिकी में यह प्रोटीन की तेजी से प्रतिलिपियां बनाने का एक प्रचलित तरीका है। इस टीके को बनाने में इस्तमाल होने वाला कच्चा माल सस्ता है और आसानी से मिलने वाला है।

कंपनी बायोलॉजिकल-ई से लिया और इसका फार्मूला एवं दे दी, ताकि हैदराबाद की नैदानिक परीक्षण भारत में उत्पादन कार्य को आगे बढ़ा। टीके के तीसरे चरण के पर्स मिल गई है, जिसके जुलाई तकी की उम्मीद है।

कॉर्बेवैक्स एम-आरएनए वायरस विषाणु वेक्टर वात्यांकों की तरह केवल स्पालक्षित करता है, लेकिन इसका क्रिया और इसकी कार्यप्रणाली अभी तक जारी नहीं है। इसमें शुद्ध किया हुआ इंजेक्शन से सीधे मनुष्य को जबकि अन्य टीकों में ऐसे अवयव एम-आरएनए एवं डीजी जो हमारे शरीर में अंदर जाकर का उत्पादन करते हैं। अधिकारी टीकों की तरह कॉर्बेवैक्स को देखा जाता है। चूंकि इसे कम लागत का उपयोग करके बनाया गया है, इसमें उपलब्ध सबसे सस्ता टीका रहा है। भारत सरकार के विशाल कार्यक्रम में यह पहली बार है, एक टीके पर विश्वास करके फटाफट है जिसे आपातकालीन उपयोग अभी स्वीकृत किया गया है। इसका 1,500 करोड़ रुपये का अंगठिम

मझौता कर रंभिक सामग्री नहीं इसका लाभ कर इसके के। अब इस लोगों को मंजूरी खत्म हो जाने और एडेनोटीके कोविड प्रोटीन को बनाने की व्यवस्था अलग वापिक प्रोटीन दिया जाता है, आनुवांशिक एवं दिए जाते हैं याइक्रोटीन अन्य कोविड युक्त में दिया गया तकनीक लिए यह देश तत्त्व होने वाला था। टीकाकरण ब सरकार ने इसकरार किया लिए अभी-करार के लिए तात्त्व भी किया टीका लगाया गर के मौजूदा

करार के मुताबिक कॉर्बेवैक्स का टीका प्रति डोज 50 रुपये की लागत पर मिल जाएगा। केंद्र सरकार इस टीके के ल्यरिंग विकास के लिए प्रमुख प्री-विलनिकल और विलनिकल परीक्षणों में सहायता भी प्रदान कर रही है, इसमें सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से 100 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि भी प्रदान की गई है। बायोलॉजिकल-ई की स्थापना डॉ डीवीके राजने वर्ष 1953 में एक जैविक उत्पाद कंपनी के रूप में की थी। वर्ष 1962 तक इसने बड़े पैमाने पर डीपीटी टीकों का उत्पादन करते हुए टीकों के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके टीकों की आपूर्ति 100 से अधिक देशों को की जाती है और इसने पिछले 10 वर्षों में ही दुनिया भर में दो अरब से अधिक खुराकों की आपूर्ति की है। भारत सरकार द्वारा इतना काविड टीके का बड़ा ऑर्डर देने की वजह टीकाकरण की आपूर्ति बढ़ाने में हो रही मुश्किलें हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने फाइजर, एस्ट्रजेनेका और मॉडना जैसी टीकों में अग्रिम भुगतान और जोखिम वाले निवेश किए थे, भारत सरकार ने सीमित ऑर्डर देने से पहले भारत में दोनों टीकों को नैदानिक परीक्षण की अधिकारिक मंजूरी मिलने तक इंतजार किया। हमारे देश को दिसंबर तक कोविड के टीकों की 200 करोड़ खुराक तक सुरक्षित करना होगा। इस लक्ष्य को देखते हुए कॉर्बेवैक्स इस अपेक्षित आपूर्ति का एक बड़े हिस्से का उत्पादन कर सकेगा। इस प्रकार से ये करार ऐतिहासिक है और भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी पूरा करता नजर आता है।

